IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

"आत्मनिर्भर भारत, डिजिटल भारत: एक समीक्षात्मक अध्ययन"

अरुण यादव
(शोध छात्र)
अर्थशास्त्र विभाग
महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी
उत्तर प्रदेश-भारत
Email id- arunyadav.bhu2013@gmail.com
Phone no.9260922204

सारांश(Abstract):-

वर्तमान समय में भारतीय अर्थव्यवस्था एक डिजिटल अर्थव्यवस्था के रूप में उभर रही है, आधुनिक समय में भारत के यूपीआई अर्थात यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस की वैश्विक प्रशंसा हो रही है साथ ही पश्चिमी देश और एशिया के कुछ देश इस प्रणाली को अपनाने पर भी ज़ोर दे रहे है, जिससे भारतीय सरकार द्वारा चलाए गए विभिन्न डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम और डिजिटल संबंधित योजनाओं की अहम भूमिका की सराहना हो रही है। बता दें कि वर्तमान समय में भारत में यूपीआई प्रणाली के माध्यम से 60% डिजिटल भुगतान का लेनदेन हुआ है जिसके कारण पिछले पांच वर्षों में लगभग पांच गुना डिजिटल भुगतान में वृद्धि हुई है अर्थात हाल ही में 'CLSA रिपोर्ट' के अनुसार भारत में डिजिटल भुगतान वित्तीय वर्ष 2021 में 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर से वित्तीय वर्ष 2026 तक एक ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर बढ़ने की संभावना है, जिससे पता चलता है, कि इस आधुनिक समय में आर्थिक विकास को गति देने के लिए डिजिटल अर्थव्यवस्था को अपनाना कितना महत्वपूर्ण हो गया है इस शोध पत्र का प्रमुख तर्क यह देने का प्रयास किया जा रहा है, कि भारतीय अर्थव्यवस्था के परिपेक्ष में डिजिटल अर्थव्यवस्था की भूमिका,संभावनाएँ तथा अवसरों को जानना बहुत ही दिलचस्प होगा, क्योंकि वर्तमान समय में विकासशील देशों में भुगतान प्रणाली में डिजिटलीकरण से आर्थिक विकास के गति में तेजी के साथ विकासात्मक लक्ष्य प्राप्त करने में सहायक हुआ है। अंततः इस शोध पत्र में वर्णनात्मक विश्लेषण के रूप मे सहायक आँकड़ों का प्रयोग करते हुए तथा सारणीबद्ध प्रस्तुतिकरण कर अपनी शोध पत्र के उद्देश्य के अनुरूप दृष्टिकोण प्रदान करने का प्रयास किया गया है।

मुख्य शब्द(keywords):- डिजिटल अर्थव्यवस्था, डिजिटल भुगतान, डिजिटल खपत(उपभोग), डिजिटलीकरण

प्रस्तावना(Introduction):-

डिजिटल अर्थव्यवस्था आधुनिक युग में व्यापक रूप से डिजिटल उपकरणों के उपयोग अर्थात उपभोग किए जाने के लिए अधिक निर्भरता होने के कारण ही डिजिटल युग को एक डिजिटल अर्थव्यवस्था के रूप में देखा जा रहा है। CLSA रिपोर्ट के अनुसार भारत में वित्तीय वर्ष 2026तक डिजिटल भुगतान एक ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ने की संभावना है अर्थात इस रिपोर्ट के अनुसार डिजिटल भुगतान वित्तीय वर्ष 2015-16 में 61 बिलियन अमेरिकी डॉलर उपभोग के 6% से बढ़कर लगभग 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर जो वित्तीय वर्ष 2020-21 में कुल उपभोग का 18%

हो गया है डिजिटल उपभोग और यूपीआई के उपयोग के विस्तार के कारण डिजिटल भुगतान 27% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि सीएजीआर(CAGR) से बढ़ेगा तथा भारत के संपूर्ण उपभोग का 30% हिस्सा केवल डिजिटल भुगतान का होगा और वही बात करें 'अभी खरीदे बाद में भुगतान करें' बीएनपीएल(BNPL-Buy Now Pay Later) प्रणाली में वह 15 से 20 अरब अमेरिकी डॉलर है, जो डिजिटल भुगतान का महज 5 से 6 प्रतिशत है और यह वित्तीय वर्ष 2026 तक पांच गुना बढ़कर 90 से 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर या डिजिटल भुगतान का लगभग 10% हो जाएगा जो भारत की बढ़ती डिजिटल अर्थव्यवस्था पर निर्भरता ये वो दक्षता को प्रदर्शित करता है। (https://bfsi.economictimes.indiatimes.com)

डिजिटल प्रोद्योगिकियों ने अर्थव्यवस्था को जिस तरह बांधने का प्रयास किया है, उसके लिए एक शब्द के रूप में "डिजिटल अर्थव्यवस्था" काफी व्यापक शब्द है। डिजिटल अर्थव्यवस्था की अवधारणा की शुरुआत लगभग सन 1995 मैं डॉन टीप्सकैट द्वारा लिखित पुस्तक: "द डिजिटल इकोनॉमी प्रॉमिस एंड पेरिल इन द एज ऑफ नेटवर्क इंटेलिजेंस" को जाता है जिसको तकनीकी आधारित आर्थिक क्रियाएं व घटनाओं का वर्णन करने के लिए विभिन्न तरीकों से इस्तेमाल हुआ है।

- **डिजिटल अर्थव्यवस्था क्या है?**

डिजिटल अर्थव्यवस्था का ताज पर ऐसे परिवेश से है जहाँ प्राचीन भुगतान प्रणाली शहर आधुनिक भुगतान प्रणाली की ओर जाना अर्थात किसी अर्थव्यवस्था में एक वस्तु के उपभोग करने के बाद उसका भुगतान करने के लिए आधुनिक प्रौद्योगिकी प्रणाली जैसे-भुगतान कार्ड, इंटरनेट आदि का प्रयोग करना या इसको बढ़ावा देना ही डिजिटल अर्थव्यवस्था कहलाता है इसी कारण इसे इंटरनेट अर्थव्यवस्था आधुनिक अर्थव्यवस्था वेब अर्थव्यवस्था के रूप में अन्य नाम से भी जाना जाता है। (https://www.google.nic.in)

- **डिजिटल भुगतान प्रणाली के स्वरूप?**

  डिजिटल भुगतान प्रणाली आधुनिक समय में दो प्रकार से किए जा सकते हैं:-

  1. **Online Digital Payment**
  2. **Off-line Digital Payment**

- **Online Digital Payment:-**जब किसी वस्तु के उपभोग हेतु भुगतान करने के लिए प्रौद्योगिकी उपकरणों का उपयोग करने के साथ-साथ लेन देन की प्रामाणिकता के अतिरिक्त एएफए(AFA) की आवश्यकता पड़ती है उदाहरण के लिए यूपीआई,इंटरनेट बैंकिंग इत्यादि।

- **Off-line Digital Payment:-**जब ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने हेतु वर्ष 2020 के अगस्त में एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में ऑफ़लाइन डिजिटल पेमेंट की शुरूआत किया गया था इसमें भुगतान करते समय इंटरनेट की आवश्यकता नहीं पड़ती अर्थात ऑफलाइन मोड के तहत कार्ड, वॉलेट और मोबाइल उपकरणों(SMS अलर्ट) का उपयोग करके भुगतान किया जाता है। इसमे एएफए(AFA) की आवश्यकता नहीं पड़ती है तथा यह सुविधा छोटे मूल्य के डिजिटल पेमेंट को ध्यान में रखकर तैयार की गई है जिसमे प्रति लेनदेन के लिमिट ₹200 तक तथा कुल ऑफ लाइन लिमिट 2000 तक है।

साहित्य समीक्षा(Literature Review):-

1. "भारतीय अर्थव्यवस्था पर डिजिटलीकरण का प्रभाव और वित्तीय साक्षरता की आवश्यकता" मृणालिनी कौल, पूर्वी माथुर (2017) किसी देश पर डिजिटलीकरण के प्रभाव का आकलन सरकार पर अर्थव्यवस्था और इसलिए समाज पर इसके प्रभाव के विचार से किया जा सकता है। हमने डिजिटलीकरण के उद्भव के साथ

प्रत्येक क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण संशोधन देखा है। डिजिटलाइजेशन ने रोजगार के नए अवसर पैदा किए हैं, भयानक क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा दिया है और साथ ही अर्थव्यवस्था के विस्तार का नेतृत्व किया है यानी देश के सकल घरेलू उत्पाद के विकास में मदद की है।

2. "डिजिटलीकरण और अर्थव्यवस्था पर इसका प्रभाव" साइमा खान, डॉ. शाजिया खान, मोहसिना आफताब (2015) पिछले कुछ वर्षों में प्रिंट स्रोतों के डिजिटल रूपांतरण में तेजी से सुधार हुआ है। रूपांतरण यह है कि डिजिटल जानकारी के साथ आने, प्रक्रिया करने, साझा करने और प्रबंधित करने के लिए डिजिटल तकनीकों को बड़े पैमाने पर अपनाने से सामाजिक परिवर्तन शुरू हुआ। रूपांतरण संरक्षण और पहुंच की एक व्यापक तकनीक है जिसके द्वारा संस्था की सभी संपत्तियों को डिजिटल रूप में फिर से तैयार किया जाता है और डिजिटल प्रारूप में उच्च गुणवत्ता वाली प्रतियां बनाई जाती हैं।
3. "डिजिटलीकरण: पर इसका प्रभाव आर्थिक विकास और व्यापार" मोइनाक मैती, पार्थजीत कयाल (2017) का प्रदर्शन सेवा क्षेत्र में सुधार हुआ 2000 के बाद से काफी आगे। आईटी में विकास और आईटीईएस संशोधित और स्वचालित व्यापार पद्धति। इस कुल मिलाकर हुआ प्रत्येक में सुधार उत्पादन और सेवाएं क्षेत्रों। भारत का सेवा क्षेत्र और MSME चरण में है भविष्य के लिए उच्च क्षमता डिजिटलीकरण के साथ विकास प्रत्येक का व्यापक विकास भारत के सेवा क्षेत्र और एमएसएमई चरण एक प्रदान करेगा व्यापार की डिग्री को बढ़ावा और भारत का हिस्सा डिजिटलीकरण की सहायता

शोध पत्र के उद्देश्य(Objective of Research paper):-

- आत्मनिर्भर भारत के डिजिटल स्वरूप स्थिति का एक समीक्षात्मक अध्ययन करना ताकि डिजिटल अर्थव्यवस्था की एक समझ विकसित किया जा सके।
- डिजिटल क्षेत्र में भारत के स्वावलंबी बनने मे होने वाली समस्या का अध्ययन करना।
- डिजिटल क्षेत्रों से संबंधित विभिन्न अवधारणा की रूपरेखा को प्रस्तुतिकरण करना।

शोध प्रविधि(Research Methodology):-

प्रस्तुत शोध पत्र लेखन में इस शोध पत्र के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए अनुसंधान अभिकल्प में वर्णनात्मक विश्लेषण के माध्यम से वर्तमान स्थितियों का स्पष्टीकरण कर वर्तमान समय के नियोजन कार्यक्रम अभियान तथा आंकड़ों के तथ्यों की व्याख्या किया गया है। अंततः प्रस्तुत शोध पत्र में द्वितीय आंकड़ों का प्रयोग किया गया है, द्वितीय आंकड़ों का संकलन हेतु विभिन्न पुस्तकों की शोध प्रबंध, विभिन्न शोध पत्र, विभिन्न सरकारी प्रकाशन, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन, विभिन्न समाचार पत्र, पत्रिकाएँ, विभिन्न इंटरनेट, वेबसाइट आदि का प्रयोग किया गया है तथा प्राप्त द्वितीय आंकड़ों को ग्राफ और अनुसूची के माध्यम से सारणीबद्ध प्रस्तुतिकरण करके धनात्मक निष्कर्ष तक पहुंचने का प्रयास किया गया है।

शोध-पत्र का अध्ययन(Study of Research Paper):-

किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए डिजिटल अर्थव्यवस्था आधुनिक युग में आर्थिक विकास की गति तथा विकासात्मक लक्ष्य को प्राप्त करने में कितना महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है इस शोध पत्र के माध्यम से यही बताने का प्रयास किया जा रहा है।

भारत में डिजिटल भुगतान प्रणाली एवं नियामक:-

- RBI **द्वारा-1.NEFT**(National electronic fund transferred)
  2.RTGS(Real time Gross Settlement)

3.भुगतान बैंक(Payment Bank)

4.Digital payment index (DPI),2018.

- NPCI द्वारा- (National Payment Corporation of India)

  इसकी स्थापना 2008 में हुआ भारत में रिटेल भुगतान और सेटलमेंट प्रणाली भुगतान के लिए एक छाता संगठन के रूप में काम करता है।

  भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 के तहत आरबीआई और भारतीय बैंक संघ (IBA) ही एक पहल है।

  कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 25 जो अब कंपनी अधिनियम 2013 की धारा आठ के तहत नॉन फॉर प्रॉफिट(Non for profit) कंपनी के रूप में शामिल हैं।

  UPMS(Unified Payment Management System) जो भारत बिल पे(BBL)ने आवृत्ति बिल पेमेंट को आसान और सुरक्षित बनाने के लिए यह एक नवाचार प्रणाली है। यह प्रणाली ग्राहकों को किसी बिल भुगतान पर चैनल या मोड के लिए स्टैंडिंग इन्स्ट्रक्शन (Standing Interaction)स्थापित करने में मदद करेगा।

  BBL(Bharat Bill Pay), NPCI की सहायक कंपनी है।

  NPCI & it's Broad:-

  1.IMPS(Immediate Payment Service**)**

  2.UPI(Unified Payments Interface**)**

  3.BHIM(Bharat Interface for Money)

  4.NSF(National Financial Switch**)**

भारत में ATM,POS, CREDIT CARD,DEBIT CARD, इत्यादि की कुल संख्या:-

डिजिटल विनियम उपकरण	संख्या(2020-21)
• एटीएम(ATM)	
Online site	1,14,045
Offline site	94,436
• Point of Sale (POS)	57,41,106
• क्रेडिट कार्डों की संख्या	6,03,97,171
• डेबिट कार्डों की संख्या	88,64,18,288

(Source: pratiyogita darpan Economics Annual report magazine 2020-21)

भारतीय परिदृश्य में:-

भारतीय परिदृश्य मैं बात करें तो हाल ही में 2021-22 नीति आयोग ने डिजिटल बैंकों पर एक रिपोर्ट जारी की है, जिसका शीर्षक है-"Digital Banks: A Proposal for Licensing & Regulatory Regime for India" इस रिपोर्ट के माध्यम से नीति आयोग ने यह बताने का प्रयास किया है, कि भारत में डिजिटल अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाने के लिए डिजिटल बैंकों के लाइसेंसिंग तथा नियामक कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाना अति आवश्यक है। इसी कारण इस रिपोर्ट का मुख्य उद्देश्य है फिनटेक जैसे उद्योगों मैं भारत को आत्मनिर्भरता के साथ अग्रणी बनाना तथा डिजिटल बैंकों के लाइसेंसिंग तथा नियामक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाना है, (https://www.drishtiias.com) इस रिपोर्ट में चार कारकों को सम्मानित किया गया है:-

- प्रवेश बाधाएं(Entry Barrier)
- प्रतिस्पर्धात्मक(Competition)
- व्यापार प्रतिबंध(Business Restrictions)
- तकनीकी तटस्थता(Technological Neutrality)

रिपोर्ट के मुख्य बिंदु निम्नलिखित है:-

1. घरेलू फिनटेक उद्योगों तथा यूपीआई से संबंधित विकासात्मक वृद्धि दर्ज की है।
2. पूर्णतया डिजिटल बैंकों के प्रयास में वैश्विक स्तर पर भारत के प्रभुत्व को स्थापित किया है।
3. यूपीआई लेनदेन में चार ट्रिलियन तक का लेनदेन प्राप्त किया गया है।

भारत सरकार द्वारा डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने हेतु प्रमुख योजनाएं:-

डिजिटल इंडिया कार्यक्रम:- डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत 1 जुलाई 2015 मैं हुई इसके माध्यम से भारत को डिजिटल आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रौद्योगिकी स्टैक के माध्यम से शिक्षा व्यापार गवर्नेंस बाज़ार आदि के क्षेत्र को कागज रहित बनाने हेतु माननीय वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की सुझाव एवं विचार से डिजिटल इंडिया वीक को हर वर्ष मनाने का निर्णय लिया गया वर्तमान में इसका आयोजन चार से 9 जुलाई 2022 तक किया जा रहा है और इस वर्ष का शीर्षक-"**Catalyzing New India Techade**"है इसका मुख्य उद्देश्य देश को डिजिटल रूप से सशक्त समाज एवं पेपरलेस अर्थव्यवस्था बनाना है, यह डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की प्रमुख पहल में से एक है डिजिटल इंडिया वीक के तहत प्रमुख पहल निम्नलिखित है:-

1. मेरी योजना मेरी पहचान
2. डिजिटल इंडिया भाषिणी
3. डिजिटल इंडिया GENESIS
4. चिप्स टू स्टार्टअप प्रोग्राम इत्यादि।

USSD code*99#योजना:-इस योजना की शुरुआत 28 अगस्त 2017 को हुआ यह मोबाइल बैंकिंग से संबंधित है इस योजना का लाभ ऐसे लोगों के लिए है जिसके पास या तो स्मार्टफोन नहीं है या वे इंटरनेट का प्रयोग नहीं करते इस मोबाइल बैंकिंग सुविधा से अधिकतर निम्न आय वर्ग अर्थात ग्रामीण लोग जुड़ सकें और घर बैठे बैंकिंग सुविधा ले सकें जिससे देश में बढ़ते डिजिटल स्वरूप को एक रूप देने में सक्षम तथा सामर्थ बनाया जा सके। भारत में डिजिटल भुगतान को सुगम बनाने हेतु कुछ प्रमुख मोबाइल वॉलेट निम्नलिखित हैं:-

1. स्टेट बैंक बड्डी
2. पे टी एम(Pym)
3. फ़ोन पे
4. पेयूमनी(Pay U Money)
5. वोडाफ़ोन एम पैसे
6. आईसीआईसीआई पैकेट
7. जिओ मनी
8. पीएनबी किट्टी
9. बरौदा एमए क्लीक
10. मोबिक्विक(Mobi Kwik)
11. आईवॉच

भारत नेट परियोजना: यह दुनिया की सबसे बड़ी ग्रामीण ब्रॉडबैंड परियोजना है, भारतनेट का लक्ष्य सभी 2.52 लाख ग्राम पंचायतों को हाई स्पीड इंटरनेट से जोड़ना है. अब तक 1.78 लाख से ज्यादा ग्राम पंचायतें ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ी जा चुकी हैं, भारत नेट परियोजना का उद्देश्य ऑप्टिकल फाइबर (Optical Fiber) के माध्यम से भारतीय गाँवों को उच्च गति ब्रॉडबैंड कनेक्शन से जोड़ना है। सर्वप्रथम तमिलनाडु में इस परियोजना के माध्यम से राज्य के सभी 12,524 ग्राम पंचायतों को जोड़ने की योजना थी।(https://www.google.com)

परियोजना के चरण:

- प्रथम चरण में, अंडरग्राउंड ऑप्टिकल फाइबर केबल लाइनों के माध्यम से ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी को एक लाख ग्राम पंचायतों तक उपलब्ध कराया गया है। इस चरण को दिसंबर, 2017 तक पूरा कर लिया गया है।
- द्वितीय चरण में , भूमिगत फाइबर, पावर लाइनों, रेडियो और उपग्रह मीडिया पर फाइबर के इष्टतम मिश्रण का उपयोग करके देश में सभी 1.5 लाख ग्राम पंचायतों को कनेक्टिविटी प्रदान की जाएगी। चरण-2 के सफलतापूर्वक क्रियान्वयन के लिये, बिजली के खंभों पर ऑप्टिकल फाइबर केबल को भी लगाया गया है।
- तीसरा चरण वर्ष 2019 से वर्ष 2023 तक पूर्ण होना है। इस परियोजना को 'मेक इन इंडिया' के तहत कार्यान्वित किया जा रहा है अतः देश में ही रोज़गार के नए अवसर विकसित होंगे। ग्रामीण और शहरी भारत के बीच के डिजिटल डिवाइड को कम करके ही देश में शत-प्रतिशत डिजिटलीकरण को प्राप्त किया जा सकता है। (https://www.drishtiias.com)

VISAKA योजना:-विशाखा योजना आरबीआई(RBI) द्वारा चलाया गया एक वित्तीय साक्षरता अभियान जो भारत को डिजिटल और कैशलेस इकोनॉमी बनाने हेतु योजना है।

प्रधानमंत्री वाणी योजना:- यह योजना सार्वजनिक स्थानों पर वाईफाई की उपलब्धता से संबंधित हैं।

भारत सरकार द्वारा डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने हेतु प्रमुख समितियां:-

1. **नचिकेत मोर समिति (2013):** भुगतान बैंक यह स्थापना हेतु यह समिति का गठन किया गया था ताकि डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिल सके।
2. **नीरज कुमार गुप्ता समिति:** आरबीआई द्वारा गठित यह समिति कैशलेस लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए है।
3. **रतन पी वतल समिति:** यह समिति " टू बूस्ट डिजिटल पेमेंट सिस्टम इन इंडिया" को बढ़ावा देने के लिए भारतीय सरकार द्वारा गठित किया गया था।

भारतीय अर्थव्यवस्था में डिजिटल अर्थव्यवस्था का लाभ (महत्त्व):-

1. भ्रष्टाचार में कमी आएगी
2. कालाबाजारी कम होगी
3. ग्रामीण विद्यार्थियों को सुविधापूर्ण शिक्षा मुहैया
4. सरकारी विभागों में ऑनलाइन कार्यप्रणाली से पारदर्शिता सुनिचित करना
5. देश का विकास तेजी से होगा ग्रामीण लोग ठगी के शिकार नहीं होंगे
6. बैंकिंग सुविधाओं का लाभ निचले स्तर तक पहुंच सुनिचित होगी।
7. सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ योग्य उम्मीदवार को मिलेगा।

डिजिटल इंडिया की हानि

- डिजिटलीकरण ने हम मनुष्यों को मशीनों पर निर्भर कर दिया है।
- हम किसी अपने से बात करने के लिए भी किसी मशीन का ही प्रयोग करते है।
- डिजिटलीकरण ने हमें एक दूसरे से सामाजिक रूप से दूर किया है।
- इंटरनेट के इस्तेमाल ने साइबर क्राइम को बहुत बढ़ावा दिया है।
- भारत में इसके प्रति कोई विशेष सावधानी नहीं बरती जाती है, जिस कारण साइबर क्राइम का खतरा बढ़ जाता है।
- डिजिटल इंडिया की सफलता के लिए इंटरनेट का प्रयोग करना ज़रूरी होता है।

आंकड़ों का विश्लेषण एवं व्याख्या(Data Interpretation & Analysis):-

आंकड़ों के विश्लेषण एवं उसकी व्याख्या से यह अनुमान लगाया जाएगा कि डिजिटल अर्थव्यवस्था की वास्तविक स्थिति का भारतीय अर्थव्यवस्था में भूमिका एवं उसके प्रभाव द्वारा निष्कर्ष और सुझावों पर विचार रखा जाएगा। उक्त आंकड़ों की व्याख्या को भी शोध पत्र के उद्देश्य के अनुसार तीन भागों में बांटा गया है:-

- **Table No.1 भारत में UPI का लेन देन नमूना**

वर्ष (YEARS)	यूपीआई द्वारा लेनदेन(आंकड़े करोड़ रुपए में)
2017	2,425
2018	24,173
2019	1,33,461
2020	2,06,462
2021	5,04,886
2022	9,60,582

. **(source: National Payments corporation of India Annual report 2021-22)**

- **Figure No.1**

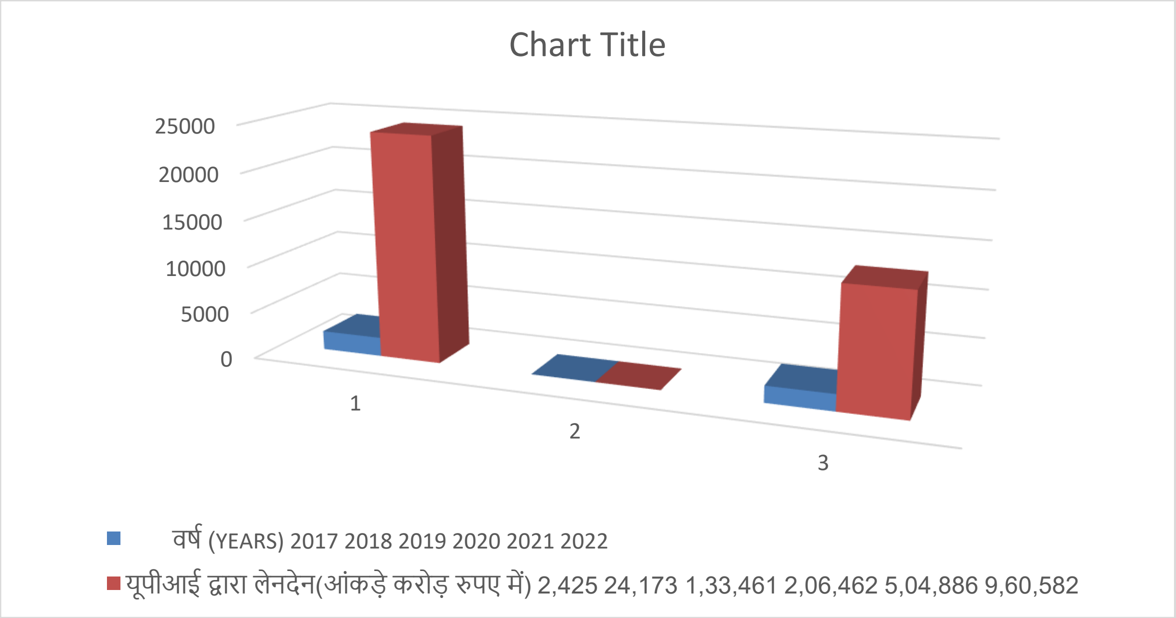

Table No.2भारत में बैंकिंग उपभोक्ता की रूपरेखा मार्च माह 2021

वर्ष(2021) के मार्च माह के आंकड़े	भारत में बैंकिंग उपभोक्ता में वृद्धि (आंकड़े लाखों में)
मार्च 18	44
मार्च 18	91
मार्च 19	142
मार्च 20	148
मार्च 21	216
नवम्बर 21	274

(Source: prepared by Author of economics survey 2021-22.

(Figure No.2 Number of Banks increase in UPI System Uses in this financial year 2021)

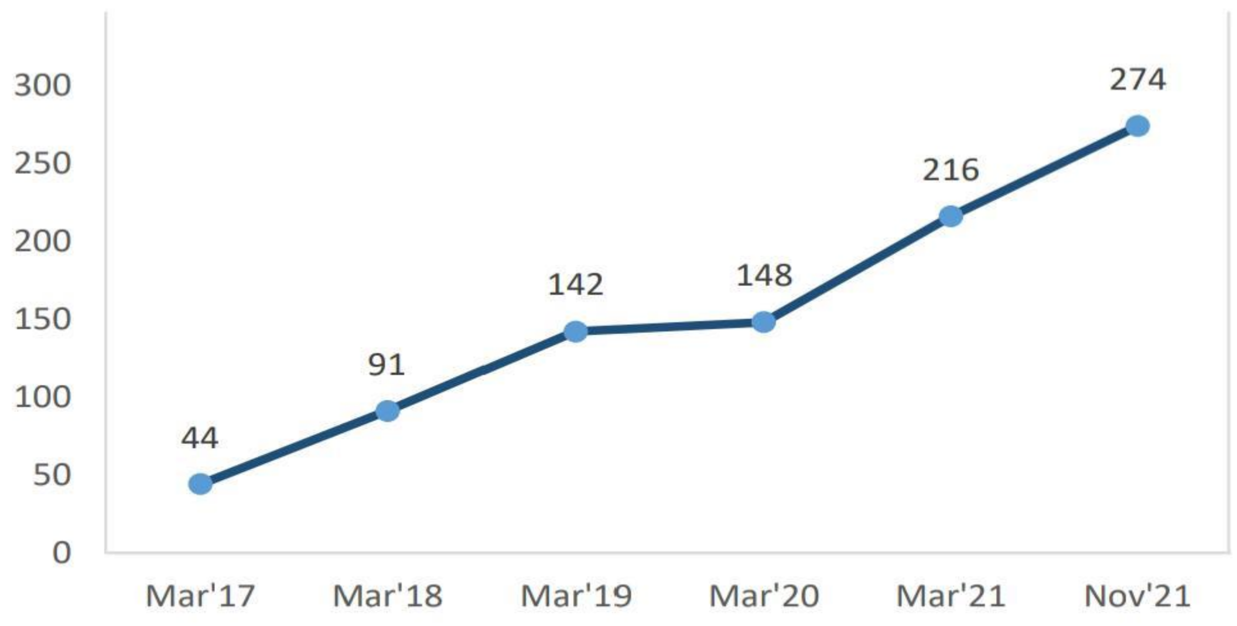

(Source: NPCI, ECONOMY SURVEY 2021-22)

Table No.3 भारत में डिजिटल उपभोगताओ की रूपरेखा 20216-2022

वर्ष (Year)	भारत में इंटरनेट उपभोक्ता की वृद्धि (आंकड़ा करोड़ों में)
2016-17	1,000
2017-18	2,000
2018-19	14,000
2019-20	25,000
2020-21	40,000
2021-22	58,000

(Source: prepared by Author of Economy Survey 2021-22.

Figure No.3 UPI payment in India Period of 2016-17to 2021-22

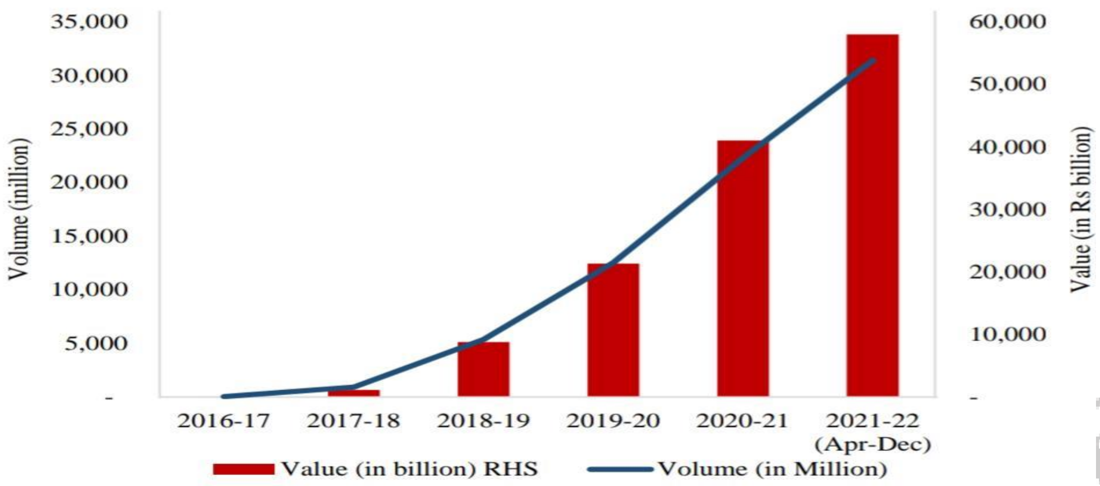

(Source: NPCI, Economy Survey,2021-22)

महत्वपूर्ण निष्कर्ष(Conclusion & Finding):-

उक्त आंकड़ों के सहायता से यह निष्कर्ष प्राप्त हो रहा है, कि भारत जैसे विकासशील देशों में इंटरनेट खपत, डिजिटल खपत और बैंकिंग उपभोक्ताओं में निरंतर वर्ष दर वर्ष वृद्धि के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था एक डिजिटल अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर हो रहा है,क्योंकि भारत में अमेरिका के बाद विश्व में इंटरनेट उपभोक्ता के स्तर पर द्वितीय स्थान है। अंततः सुव्यवस्थित एवं सरल भुगतान प्रणाली एवं डिजिटल बैंकिंग संस्था अभियान और वर्तमान प्रौद्योगिकी स्टैक के माध्यम से शिक्षा के साथ-साथ कैशलेस इकोनॉमी बनाने हेतु परियोजनाओं का विकासात्मक क्रियान्वयन करना अति आवश्यक है, ताकि भारत जैसे विकासशील देशों को भी डिजिटलीकरण के माध्यम से वैश्विक डिजिटल गुरु अर्थव्यवस्था बनाया जा सके।

सुझाव(Suggestions):-

1.इस वर्तमान डिजिटल युग में प्रासंगिक बन्ने रहने के लिए आर्थिक नीतियां योजनाएं स्वयं डिजिटलीकरण की ओर अग्रसर होने वाली होनी चाहिए।

2.डिजिटल भुगतान डिजिटल बैंकिंग आदि हेतु साक्षरता अभियान चलाया जाना चाहिए ताकि कैशलेस इकोनॉमी बनाया जा सके।

3.ई-कॉमर्स नीति को और सरल सहज और सुरक्षित बनाने की आवश्यकता है,क्योंकि डिजिटलीकरण और साइबर क्राइम मैं प्रत्यक्ष संबंध होता है।

4.वर्तमान डिजिटलीकरण के योजनाओं से ग्राहकों के आत्मविश्वास डिजिटल एवं बैंकिंग आदत आदि द्वारा दिनचर्या का भागीदार बनना चाहिए।

संदर्भ ग्रंथ सूची(References List):-

1. Rani Suman(2016). Digital India: Unleashing Prosperity. Indian Journal of AppliedResearch,Volume-6,Issue4,pp187-189
2. Midha Rahul (2016). Digital India: Barriers and Remedies. International Conference on Recent Innovations in Sciences, Management, Education and Technology. Retrieved from http:// data. Conference world .in/ICISMET/P256-261. Pdf.
3. Gupta Neeru and Arora Kirandeep (2015). Digital India: A Roadmap for the development of Rural India. International Journal of Business Management ,vol(2)2, pp1333-1342. Retrieved from www. Ijbm. Co .in
4. Kadam Avinash (2015). Why cyber security is important for digital India. Retrieved from http://www.firstpost.com/business/why-cyber-security-is-important-for-digital-india-2424380.html
5. Digital India. Unlocking the trillion Dollar Opportunity: ASSOCHAM-Deloitte report, November 2016.Retrieved from www.assocham.org.
6. https://en.wikipedia.org/wiki/Digital_India.
7. Ramija, B. (2018), "Research article Indian Digital Economy – Opportunities and Challenges", International Journal of Current Research Vol. 10, Issue, 10, pp.74338-74344, October, 2018
8. 8.Patra.s, "Estimate impact & control of blank money in India " .Asian resonance, volume 5 issue 3,PP-60 to 66.
9. नीति आयोग की रिपोर्ट –"Digital banks: A proposal for licensing and regulatory regime for India"2021-22.
10. https://www.npci.org.in//Digital payment adoption in india
11. Economy survey annual report 2021-22.
12. https:// www.wikipedia.org.in/:22Nov.,2022
13. https://www.google.nic.in/:29oct.,2022

डिजिटल बैंकिंग और वित्तीय संबंधित प्रमुख संक्षेपाक्षर(Abbreviations):-

- **AEPS-** Aadhar Enabled payment system
- **APBA**- Aadhar payment bridge system
- **BBPS**- Bharat Bill payment system
- **CBS**- core Banking system
- **CIDR**- central Identities data repository
- **CTS-** Cheque Transaction System
- **DNS-** Domain name system

- **EFTPOS-** Electronic fund transfer at point of sale
- **HCE-** Host Card Emulation
- **IMPS-** Interbank mobile payment system
- **MMID-** Mobile money Identifier
- **MPIN-** Mobile personal identification number
- **NACH-** National Automated clearing house
- **PAC-** Personal access code
- **PSPs-** Payment support providers
- **USSD-** Unstructured supplementary service Data
- **UIDAI-** Unique Identification Authority of India
- **VPA-** vertical Payment address
- **AFA-** Additional factor of Authentication.